भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 209

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

209. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंक परस्पर स्वतंत्र ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिकृति बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न बैंकों के बीच ऐसे ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोगों की अंतर संचालनीयता भविष्य में समस्या पैदा कर सकती है;

(ग) क्या सरकार की बैंकिंग क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग में मानकीकरण और अंतर संचालनीयता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों के लिए दिशानिर्देश बनाने अथवा एक मॉडल सामान्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म विनिर्दिष्ट करने की मंशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने यह सूचित किया है कि वर्तमान में केवल कुछेक बैंक छोटे पैमाने पर ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, बैंकों के बीच ऐसे प्लेटफार्म की अंतर परिचालनीयता के संबंध में वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।

इसके अलावा, इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीडीआईसी) प्राइवेट लिमिटेड, जिनका पूर्ववर्ती नाम इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (आईबीबीआईसी) प्राइवेट लिमिटेड था, को भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में डिजिटल समाधानों का पता लगाने, तैयार करने और लागू करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगमित किया गया है। वे वर्तमान में ब्लॉकचेन के संबंध में घरेलू साख पत्र (एलसी) जारी करने को इसके एक उपयोग के रूप में लागू करने की संभावना पर कार्य कर रहा है। सहायता संघ में भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 18 अग्रणी बैंक शामिल हैं।

रिज़र्व बैंक इन्नोवेशन हब (आरबीआईएच) ने फाइनेंशियल इको सिस्टम के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म की अंतर परिचालनीयता के विचार की अवधारणा तैयार की है और बैंकों, डीएलटी फेब्रिक भागीदारों, डीएलटी एप्लिकेशन लेयर भागीदारों और फिनटेक स्टार्ट अप के साथ एक अवधारणा प्रमाण (पीओसी) का सफल अभ्यास किया है।

(ग) और (घ): बैंकों के लिए एकसमान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मॉडल प्लेटफार्म निर्धारित करने और दिशानिर्देश तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****